



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10500

एएफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 39747 वर्ष 2025

मोहम्मद शहजाद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: श्री कुलदीप कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. यह आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदक द्वारा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या 2, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। विविध मुकदमा संख्या 548/2024 (श्रीमती शाजिया खान और अन्य बनाम मोहम्मद शहजाद) में डंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "सीआर.पी.सी." कहा गया है) की धारा 128 के तहत पारित आदेश, पुलिस स्टेशन - बन्ना देवी, जिला अलीगढ़, जिसके द्वारा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने आवेदक के विरुद्ध भरण-पोषण के बकाया की वसूली के लिए अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वसूली/गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। यह वारंट भरण-पोषण मामले संख्या 1111/2017 (श्रीमती शाजिया खान और अन्य बनाम मोहम्मद शहजाद) में धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत पारित किया गया था।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप कुमार और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया। राज्य की ओर से और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का अध्ययन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदक के विरुद्ध पारित आदेश के अनुसरण में, धारा 128 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में, आवेदक के विरुद्ध वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **रजनेश बनाम नेहा और अन्य (2021) 2 एससीसी 324** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ राजनेश (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर भरण-पोषण के आदेशों को लागू किया जा सकता है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय ने दिनांक 25.04.2024 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1235/2024 में पारित आदेश के माध्यम से आवेदक को संरक्षण प्रदान किया था, इस शर्त के अधीन कि वह प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को 10,000/- रुपये प्रति माह और प्रतिवादी पक्ष संख्या 3 को 5,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करेगा। इस न्यायालय ने आवेदक को भरण-पोषण की बकाया राशि का 50% एक माह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था, और शेष 50% भरण-पोषण राशि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 और 3 को 25 जून, 2024 से शुरू होने वाली तीन समान मासिक किस्तों में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह भी *अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्देश दिया गया था कि उक्त भुगतान में चूक होने की स्थिति में, प्रधान न्यायाधीश 10% ब्याज सहित बकाया राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्वान ए.जी.ए. यह कहा गया है कि चूंकि उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध वसूली वारंट जारी करने का विवादित आदेश उचित है। हालांकि, विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक की गिरफ्तारी भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली के लिए की जाएगी। विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य से भी इनकार नहीं करते कि धारा 125(3) और 128 सीआरपीसी के तहत बकाया भरण-पोषण की वसूली के लिए कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि भरण-पोषण आदेशों को **रजनेश (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के मददेनजर लागू किया जा सकता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

5. प्रस्तावित आदेश के मददेनजर, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 और 3 को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनेश (उपरोक्त)** मामले में अनुच्छेद 132 में भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन/निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

(ई) भरण-पोषण आदेशों का प्रवर्तन/निष्पादन

132. भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि भरण-पोषण का आदेश या डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28-ए; घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(6); और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत लागू की जा अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकती है, जैसा भी लागू हो। भरण-पोषण का आदेश सिविल न्यायालय के धन डिफ्री के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से धारा 51, 55, 58, 60 को आदेश 21 के साथ पढ़ा जाए।”

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) में भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए वारंट जारी करने का तरीका बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) इस प्रकार है:

"125(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे आदेश दिया गया है, पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, जुर्माने की वसूली के लिए निर्धारित तरीके से, और ऐसे व्यक्ति को, प्रत्येक माह के भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय के लिए दिए जाने वाले भत्ते के पूरे या किसी भाग के लिए, वारंट के निष्पादन के बाद भी बकाया रहने पर, एक माह तक या भुगतान होने तक (यदि पहले हो जाए) कारावास की सजा दे सकता है;

बशर्ते कि इस धारा के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि देय होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायालय में ऐसी राशि वसूलने के लिए आवेदन न किया जाए;

इसके अलावा, यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहने की शर्त पर उसका भरण-पोषण करने की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके द्वारा बताए गए इनकार के किसी भी कारण पर विचार कर सकता है, और ऐसी पेशकश के बावजूद इस धारा के तहत आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने का कोई उचित कारण है।

स्पष्टीकरण.- यदि कोई पति किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है या रखैल रखता है, तो यह उसकी पत्नी के उसके साथ रहने से इनकार करने का उचित कारण माना जाएगा।”

8. ऊपर उद्धृत प्रावधान का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भरण-पोषण के बकाया की वसूली जुर्माने की वसूली के तरीके से की जा सकती है। जुर्माने की वसूली के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया धारा 421 सीआरपीसी के तहत दी गई है, जो नीचे उद्धृत है:

421. जुर्माना वसूलने का वारंट-(1) जब किसी अपराधी को जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई हो, तो सजा सुनाने वाला न्यायालय जुर्माना वसूलने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों तरीकों से कार्रवाई कर सकता है, अर्थात् वह-

(क) अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि वसूलने का वारंट जारी कर सकता है;

(ख) जिले के कलेक्टर को वारंट जारी करना, उसे बकाया राशि को भू-राजस्व के रूप में चूककर्ता की चल या अचल संपत्ति, या दोनों से वसूल करने के लिए अधिकृत करना;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बशर्ते कि, यदि सजा में यह निर्देश हो कि जुर्माने का भुगतान न करने पर अपराधी को कारावास दिया जाएगा, और यदि अपराधी ने जुर्माने का पूरा भुगतान कर दिया है, तो कोई भी न्यायालय ऐसा वारंट जारी नहीं करेगा, जब तक कि वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक न समझे, या जब तक कि उसने धारा 357 के तहत जुर्माने में से व्यय या मुआवजे के भुगतान का आदेश न दिया हो।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के खंड (क) के तहत जारी वारंटों के निष्पादन के तरीके को विनियमित करने और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के संबंध में अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे के त्वरित निपटान के लिए नियम बना सकती है।

(3) जहां न्यायालय उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत कलेक्टर को वारंट जारी करता है, तो कलेक्टर बकाया भूमि राजस्व की वसूली से संबंधित कानून के अनुसार राशि वसूल करेगा, जैसे कि ऐसा वारंट उस कानून के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र हो;

बशर्ते कि इस प्रकार के किसी भी वारंट को अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा।”

[जोर दिया गया]

9. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए वारंट जारी किया जाना है, जिसे धारा 421 सीआरपीसी के तहत निर्धारित तरीके अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से निष्पादित किया जाना है। धारा 421 सीआरपीसी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। वारंट के निष्पादन के बाद बकाया राशि जमा न करने पर ही कारावास की सजा दी जा सकती है।

10. धारा 125(3) सीआरपीसी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सबसे पहले, भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली/भरण-पोषण आदेश को जुर्माने की वसूली के तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और यदि वारंट निष्पादित नहीं किया जाता है या आंशिक रूप से निष्पादित किया जाता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को, भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिए जाने पर, प्रत्येक माह के भरण-पोषण भत्ते, अंतरिम भरण-पोषण, या कार्यवाही के खर्चों के पूरे या किसी भाग के लिए कारावास की सजा दे सकता है, जैसा भी मामला हो, जो वसूली वारंट के निष्पादन के बाद भी बकाया रहता है। इस प्रकार, वसूली और गिरफ्तारी वारंट का एक साथ जारी करना दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिकल्पित नहीं है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश भी ऐसी किसी प्रथा का उल्लेख नहीं करते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में अपनाया गया है।

11. इस न्यायालय ने कई मामलों में यह देखा है कि पारिवारिक अदालतों द्वारा गिरफ्तारी वारंट के साथ वसूली वारंट जारी करने के आदेश पारित किए जा रहे हैं और कुछ मामलों में गैर-जमानती वारंट भी जारी किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों और राजनेश (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है। इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए और भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली कानून द्वारा निर्धारित तरीके से की जानी चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) में स्वयं यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया है, वह आदेश का पालन न करने का कारण बता सकता है, क्योंकि धारा 125(3) दंड प्रक्रिया संहिता की प्रारंभिक पंक्तियों में कहा गया है कि "यदि कोई व्यक्ति, जिसे भरण-पोषण का आदेश दिया गया है, पर्याप्त कारण बताए बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है..." इस प्रकार, राशि का भुगतान न करने का पर्याप्त कारण बताया जा सकता है। भरण-पोषण/अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया में सबसे पहले भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश प्राप्त व्यक्ति को नोटिस जारी करना शामिल होना चाहिए। इसके बाद, यदि पर्याप्त कारण नहीं बताया जाता है, तो जुर्माने की वसूली के लिए वारंट उसी प्रकार जारी किए जा सकते हैं जैसे जुर्माना वसूलने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के **रजनेश (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय में बताया गया है, प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। भरण-पोषण के बकाया की वसूली के लिए कोई अन्य प्रक्रिया, जिसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) और 421 तथा सर्वोच्च न्यायालय के **रजनेश (उपरोक्त)** मामले के फैसले के अनुच्छेद 132 के तहत नहीं किया गया है, का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

13. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (जिसे आगे "1984 का अधिनियम" कहा गया है) में भी उस प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसका पालन पारिवारिक न्यायालयों को अपने समक्ष कार्यवाही का निर्णय करते समय करना होता है। 1984 के अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित प्रावधान है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“10. सामान्यतः प्रक्रिया - (1) इस अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन कार्यवाही को छोड़कर] मुकदमों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे और संहिता के उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, पारिवारिक न्यायालय को सिविल न्यायालय माना जाएगा और उस न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(2) इस अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उसके अधीन बनाए गए नियम, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय IX के अधीन कार्यवाही पर लागू होंगे।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में कुछ भी पारिवारिक न्यायालय को किसी मामले में समझौता करने के उद्देश्य से अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगा। मुकदमे या कार्यवाही के विषयवस्तु के संबंध में या एक पक्ष द्वारा लगाए गए और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत तथ्यों की सत्यता के संबंध में।”

14. यद्यपि, 1984 के अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) परिवार न्यायालय को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वतंत्रता देती है, परन्तु यह स्वतंत्रता केवल मुकदमे या कार्यवाही के विषयवस्तु के संबंध में समझौता करने या एक पक्ष द्वारा लगाए गए और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत तथ्यों की सत्यता का पता लगाने तक ही सीमित है। 1984 के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिवार न्यायालय को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार देता हो, सिवाय अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उस तरीके के जो दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित हो, जैसा भी मामला हो।

15. 1984 के अधिनियम की धारा 18 डिक्री और आदेशों के निष्पादन का प्रावधान करती है।

1984 के अधिनियम की धारा 18 नीचे दी गई है:

“18. डिक्री और आदेशों का निष्पादन.-(1) किसी पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन आदेश के अलावा] का वही बल और प्रभाव होगा जो किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश का होता है और उसका निष्पादन उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा डिक्री और आदेशों के निष्पादन के लिए निर्धारित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के तहत परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निष्पादन उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(3) किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन या तो उस परिवार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसने इसे पारित किया है या किसी अन्य परिवार न्यायालय या साधारण दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे निष्पादन के लिए भेजा गया है।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. 1984 के अधिनियम की धारा 18(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के अध्याय IX के अंतर्गत पारित आदेश का निष्पादन दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जा सकते। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा निर्धारित तरीके से ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

17. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अनुच्छेद 21 पवित्र है और हमारे संविधान की मूल संरचना का निर्माण करता है। किसी व्यक्ति को प्रदत्त इस मौलिक अधिकार को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा निर्धारित तरीके से, न कि न्यायालयों द्वारा कानून की गलत व्याख्या के आधार पर।

18. इस न्यायालय की राय में, गिरफ्तारी वारंट जारी करना न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और स्वयं वैधानिक कानून की गलत व्याख्या है, बल्कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, जो कि सरासर अवैध है।

19. भरण-पोषण देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपराध करने वाले व्यक्ति के समान नहीं माना जाना चाहिए। भरण-पोषण के आदेशों को लागू करने में न्यायालयों द्वारा उनकी अत्यधिक तत्परता के कारण उनकी व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, भले ही न्यायालय अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यायालय के आदेश के अनुसार भरण-पोषण की बकाया राशि का जानबूझकर भुगतान नहीं किया गया है। न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी वारंट जारी करने का तरीका न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की गरिमा का हनन करता है जिसे गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष इस प्रकार पेश किया जाता है जैसे उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो।

20. **रजनेश (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी न्यायालयों को विधिवत सूचित कर दिए गए हैं, और इनका उल्लंघन अनदेखा नहीं किया जा सकता।

21. एक अन्य मुद्दा, जो इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान उठाया गया है, वह है भरण-पोषण के आदेशों का निष्पादन उसी प्रकार से किया जाना, जिस प्रकार से धन संबंधी डिक्री का निष्पादन किया जाता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनेश (उपरोक्त)** मामले में निर्धारित किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने, पैरा 132 में दिए गए निर्देशों पर भरोसा करते हुए, तर्क दिया है कि धारा 125(3) सीआर.पी.सी. के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 51, 55, 58 और 60, के साथ आदेश XXI सी.पी.सी. का पालन किया जाना चाहिए।

22. जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1984 के अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत कार्यवाही के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय (न्यायालय) नियम, 2006 (जिसे आगे "यू.पी. परिवार न्यायालय नियम" कहा गया है), अध्याय VIII में परिवार न्यायालय के आदेशों के निष्पादन का प्रावधान है। संदर्भ के लिए, यू.पी. के अध्याय VIII देखें। पारिवारिक न्यायालय नियम, नीचे दिए गए हैं:

"35. आदेशों का निष्पादन.- दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत याचिका पर पारित आदेशों को छोड़कर, सभी मामलों में पारित आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत पारित आदेशों पर दंड प्रक्रिया संहिता के आदेशों के निष्पादन के प्रावधान लागू होंगे।

36. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत भरण-पोषण भत्ता के लिए पारित आदेश को न्यायालय द्वारा धारा 60 और आदेश 21 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन कुर्क करके निष्पादित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उक्त संहिता की धारा 125 की उपधारा (3) में दिए गए वसूली के तरीके का भी उपयोग किया जा सकता है।

37. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VII की धारा 125/126 के अंतर्गत आवेदन उस स्थान पर दाखिल किया जा सकता है जहां पत्नी, नाबालिग बच्चा, माता-पिता, जैसा भी मामला हो, निवास करते हैं।

38. धारा 125 के अंतर्गत अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन लंबित है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत धारा 126 के तहत किसी भी प्रकार की कार्यवाही को अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थगित या निलंबित करने का आधार नहीं माना जाएगा। इस संहिता की धारा 125 या 126 के तहत मुख्य कार्यवाही को स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता है।

39. किसी भी बकाया राशि की वसूली के लिए लंबित निष्पादन कार्यवाही में, पारिवारिक न्यायालय कोई नया मामला दर्ज नहीं करेंगे। लंबित निष्पादन मामले में बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदन ही राशि की वसूली हेतु पर्याप्त होगा।”

24. ऊपर उद्धृत नियम 36 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 60 और आदेश XXI के तहत वेतन कुर्क करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया, धारा 125 सीआर.पी.सी. की उपधारा (3) में दी गई वसूली विधि के अतिरिक्त है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि धारा 125 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत कार्यवाही में भरण-पोषण बकाया की वसूली हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 125(3) सीआर.पी.सी. के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के समान है।

25. सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनेश (उपरोक्त)** मामले पर विचार करते समय केवल दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण प्रदान करने/भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों पर ही विचार नहीं किया, बल्कि अन्य कानूनों के अंतर्गत भी विचार किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की व्याख्या करना गलत होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों के अनुच्छेद 132 में 'सकता है' शब्द का प्रयोग किया है और यह प्रयोग उन विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिनके तहत पीड़ित व्यक्ति भरण-पोषण की मांग कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. इस प्रकार, यह निःसंदेह सत्य है कि उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 और आदेश XXI के अनुसार वेतन कुर्क करने का प्रावधान करते हैं; हालांकि, यह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई वसूली की नियमित विधि के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, नियम 36 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 और आदेश XXI के अनुसार वेतन कुर्क करने का प्रावधान करता है और उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण-पोषण का आदेश लागू किया जाना है, वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है।

27. न्यायालय की राय में, उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियमों के नियम 36, धारा 60 सी.पी.सी. और सी.पी.सी. के आदेश XXI के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रावधान केवल वेतन पर ही लागू होंगे, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के नियम 48 और 48-ए के अंतर्गत प्रावधानित है। डिक्री के निष्पादन से संबंधित संपूर्ण अध्याय लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता भरण-पोषण के बकाया की वसूली/भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन के संबंध में काफी विस्तृत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विशेष रूप से धारा 60 और आदेश XXI को वेतनभोगी व्यवसायों के लिए वसूली के नियमित तरीकों के अतिरिक्त नियम 36 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अतः, आवेदक का यह तर्क कि वसूली केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करके ही की जा सकती है, वह भी धन संबंधी डिक्री के निष्पादन के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम और नियमों तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप नहीं है।

28. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भरण-पोषण के बकाया की वसूली के लिए कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। अतिरिक्त अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या 2, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.09.2025 को विविध मुकदमा संख्या 548/2024 (श्रीमती शाजिया खान और अन्य बनाम मोहम्मद शहजाद) में धारा 128 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश, पुलिस स्टेशन - बन्ना देवी, जिला अलीगढ़, को निरस्त किया जाता है। मामले को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या 2, अलीगढ़ को वापस भेजा जाता है, ताकि वे भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन के लिए आवेदन पर विधिवत रूप से वैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्णय लें।

16 जनवरी 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।